Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

10 साल सुशासन के

10 साल कुशासन के

Research Team

Abhay Singh
Research Associate
Dr Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

Manujam Pandey
Dr Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

Design

Ajit Kumar Singh
Dr Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

विषय सूची

1	भूमिका	**4**
2	10 साल कुशासन के, 10 साल सुशासन के	**5**
3	देश के विकास और कांग्रेस की हताशा के दस साल **- विश्व प्रमोद**	**10**
4	बीजेपी और कांग्रेस में किसने लोकतंत्र को सबसे ज्यादा रौंदा? 55 बनाम 10 साल के इतिहास से समझें **- देवेन्द्र कश्यप**	**16**

भूमिका

2004 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अपनी भ्रष्ट व्यवस्था के चलते भारत के विकास को बाधित रखा. कांग्रेस के दस वर्ष ऐसे रहे जिसे उसने गंवा दिया. 2004 से 2014 तक भारत दुनिया की दसवीं अर्थव्यवस्था बनी रही लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है.

2014 से पहले कांग्रेस के शासनकाल में लोगों के मन में निराशा बैठ गई थी कि और जनता को लगता था कि हमारे एक वोट से क्या ही होगा? क्योंकि कांग्रेस की सरकारें सिर्फ भ्रष्टाचार, घोटाले और तुष्टिकरण में ही जुटी रहती थी और आम लोगों के जीवन में परिवर्तन हो इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। उनकी तो सोच ही थी कि जब दिल्ली से एक रूपए जाते हैं तो बीच में ही बिचौलिए उसे लूट लेते थे, लेकिन वर्तमान में देशवासियों को उनके एक वोट की ताकत का पता चल गया है। 2014 में इसी एक वोट की ताकत से जनता ने मोदी सरकार बनाई और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में बीते 10 वर्षों से विकास की गंगा अनवरत बह रही है। यही वजह है कि 2019 में भी लोगों ने बीजेपी को पहले से ज्यादा बहुमत दिया और अब 2024 में तीसरी बार जनता अपने एक वोट की ताकत से बीजेपी को 400 से अधिक सीटें देने का मन बना चुकी है।

आज वैश्विक संस्थाएं भारत की प्रगति को रेखांकित कर रही हैं. केवल अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, ग्रामीण भारत का विकास, समृद्ध पूर्वोत्तर, नई शिक्षा नीति, अन्तरिक्ष मिशन आदि अनेक क्षेत्रों में सर्वस्पर्शी विकास देखने को मिल रहा है.

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हमेशा चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को तय करने और निर्धारित समय सीमा से पूर्व उन्हें प्राप्त करने में विश्वास रखती है. इस ई पुस्तक के माध्यम से कांग्रेस के दस वर्ष और बीजेपी के दस वर्ष का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है.

डॉ अनिर्बान गांगुली

चेयरमैन - डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन,

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन से पिछले 10 साल में देश ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं.

1 – अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण

2 - कश्मीर से धारा 370 हटाना

3 - करीब 25 करोड़ देशवासी गरीबी रेखा से बाहर आए

4 - भारत 10वीं से पांचवीं अर्थव्यवस्था बना

5 - कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित

6 - राजधानी दिल्ली में देश के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित म्यूजियम खोला गया

7 - साहिबज़ादों की याद में वीर बाल दिवस घोषित

8 - भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया

9 - विभाजन की विभीषिका को याद करते हुए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित

10 - चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर झंडा फहराने वाला पहला देश बना भारत

11 - G-20 सम्मेलन का सफल आयोजन

12 - भारत ने एशियाई खेलों में पहली बार 100 से अधिक मेडल जीते

13 - भारत, दुनिया में सबसे तेज़ी से 5G रोलआउट करने वाला देश बना

14 - 3 दशक बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित

15 - तीन तलाक के विरुद्ध कड़ा कानून

16 - पड़ोसी देशों से आए पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने हेतु CAA

17 - वन रैंक वन पेंशन को भी लागू किया

18 - भारतीय सेना में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति

19 - GST के रूप में एक देश एक टैक्स कानून

- वर्ष 2014 में कांग्रेस की सरकार के दौरान देश के अंदर मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 थी, जो अब बढ़कर 692 हो चुकी है.
- एम्स की संख्या बढ़कर 24 हो चुकी है, जो 2014 में केवल 6 थी.
- 2014 तक देश में 723 यूनिवर्सिटी थीं जो बढ़कर 1472 हो चुकी हैं.
- 2014 तक देश में 16 आईआईटी संस्थान थे जो बढ़कर 23 हो चुके हैं.
- 2014 तक देश में 13 आईआईएम थे जो अब 20 हो चुके हैं.
- 2014 तक देश में एयरपोर्ट की संख्या 74 थी जो बढ़कर 149 हो गई.

- 2014 में भारत की बिजली उत्पादन क्षमता 2.34 लाख मेगावाट थी जो बढ़कर 4.17 लाख मेगावाट हो गई.
- 2014 तक देश में 13 करोड़ गैस कनेक्शन थे जो बढ़कर 31 करोड़ हो गए.
- 2014 तक देश में नेशनल हाईवे की पहुंच 91,287 किमी तक थी जो 1.44 लाख से ज्यादा हो गई.
- 2014 तक देश में रेल मार्गों का 21,614 किमी हिस्सा ही इलेक्ट्रिक लाइन से जुड़ा था जो बढ़कर 58,812 किमी तक पहुंच गया.
- बैंकों का NPA जो कभी डबल डिजिट में होता था वह आज लगभग 4 प्रतिशत है.
- उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेन्स कॉरिडोर का विकास.
- पिछले एक दशक के दौरान मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में 5 गुना बढ़ोतरी हुई.
- पहले भारत खिलौने आयात करता था आज मेड इन इंडिया खिलौने निर्यात कर रहा है.

- वन और पर्यावरण विभाग से क्लीयरेंस मिलने में जहां पहले 600 दिन लगते थे वहीं आज 75 दिन से भी कम समय लगता है.

• डिजिटल इंडिया की सफलता के कारण आज दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल लेनदेन का 46 प्रतिशत भारत में होता है.

• अब तक 34 लाख करोड़ रुपए डीबीटी से ट्रांसफर.

• जनधन आधार मोबाइल (JAM) के कारण करीब 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी सिस्टम से बाहर हुए हैं.

• आयुष्मान भारत के तहत लगभग 53 करोड़ लोगों की डिजिटल हेल्थ आईडी

- 4 करोड़ 10 लाख गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिला
- 10 करोड़ उज्ज्वला के गैस कनेक्शन पूरे हुए
- 11 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक हर घर जल के तहत पहली बार पाइप से शुद्ध पानी
- कोरोना काल से ही 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है
- देश की लगभग 2 लाख गांव पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा चुका है

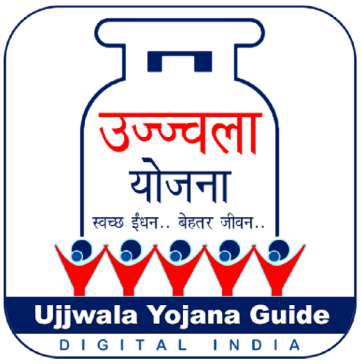

- देश में 10 हजार किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाई गई
- साल 2014 से पहले केवल 21,000 किलोमीटर तक रेल लाइन का विद्युतीकरण हुआ था, जबकि आज यह आंकड़ा 37,000 किलोमीटर तक पहुंच गया है.
- 5 शहरों तक सीमित मेट्रो की सुविधा आज 20 शहरों में है, 25 हजार किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक बिछाए गए.
- 39 से ज्यादा रूट्स पर वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है.
- जन-औषधि केंद्रों से मरीजों के करीब 28 हजार करोड़ रुपए बचे, किडनी मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस अभियान
- 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ चुकी हैं
- 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का अभियान
- मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया
- महिलाओं को पहली बार सशस्त्र बलों में परमानेंट कमीशन किया गया

- पहली बार सैनिक स्कूलों और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिला कैडेट्स को प्रवेश आज महिलाएं फाइटर पायलट भी हैं और नौसेना के जहाज को भी पहली बार कमांड कर रही हैं
- मुद्रा योजना के तहत जो 46 करोड़ से ज्यादा लोन दिए गए हैं उनमें करीब 31 करोड़ से ज्यादा लोन महिलाओं को मिले हैं
- पहली बार देश में कृषि निर्यात नीति
- पिछले 10 वर्षों में लगभग 18 लाख करोड़ रुपए MSP के रूप में धान और गेहूं की खेती करने वाले किसानों को मिले हैं.
- पीएम-किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 2 लाख 80 हज़ार करोड़ रुपए किसानों को मिल चुके है
- पौने दो लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र स्थापित
- लगभग 8 हज़ार किसान उत्पादक संघ - FPO बनाए जा चुके हैं
- सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की गई

- देश में पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया गया
- जम्मू कश्मीर में सुरक्षा का वातावरण
- नॉर्थ-ईस्ट में अलगाववाद की घटनाओं में भारी कमी
- नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र घटे हैं और नक्सली हिंसा में भी भारी गिरावट हुई
- बीते 10 वर्षों में 11 नए सोलर पार्क बन चुके हैं
- भारत की पहली वेहिकल स्क्रैपेज पॉलिसी
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई
- स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए 14 हज़ार से अधिक पीएम श्री विद्यालयों पर हो रहा काम
- इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत 10 हज़ार अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए गए

देश के विकास और कांग्रेस की हताशा के दस साल

- विश्व प्रमोद

नरेंद्र मोदी सरकार दस वर्ष पूरे कर रही है. इस अवधि में देश का अभूत पूर्व विकास हुआ है. भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया. तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की दिशा में प्रयास तेज हो चुके हैं. पांच सौ वर्षों का सपना साकार हुआ है. अयोध्या धाम में भव्य श्री राम मन्दिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं.

दूसरी तरफ कांग्रेस हताशा निराश है. कुछ समय पहले उसे तीन राज्यों मे पराजय का सामना करना पड़ा. राजस्थान छत्तीसगढ़ उसके हांथ से निकल गए. बिहार में इंडी की जगह एनडीए की सरकार बन गई. राहुल गांधी की भारत जोड़ों और न्याय यात्रा फ्लॉप रही. काग्रेस भाजपा और मोदी का विरोध करते करते देश हित के विरुद्ध चली जाती है. इससे उसकी विश्वसनीयता रसातल पर पहुँच रही है. मोदी

सरकार की नौंवी वर्षगांठ के ठीक पहले पापुआ न्यू गिनी ने उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था। गवर्नर जनरल सर बाब दबाई ने पीएम मोदी को ग्रैंड कैम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहु दिया। फिजी के प्रधानमंत्री सितीवेनी राबुका ने 'कम्पैनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी' से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। चुनिंदा गैर फिजी नागरिकों को यह सम्मान दिया गया है। नरेंद्र मोदी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगभग एक दर्जन सम्मान मिल चुके हैं। आज देश-विदेश में मोदी मोदी की गूंज सुनाई देती है और वे एक वैश्विक नेता के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं।

कोरोना महामारी का प्रकोप रहा। इसने दुनिया के विकसित देशों को भी हिला कर रख दिया। सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ। इससे अभी संभलने का प्रयास चल रहा था, तभी रूस-यूक्रेन संकट सामने आ गया। इन सभी कारणों से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है।

विश्व की परिस्थितियां प्रतिकूल रही हैं। दुनिया का कोई देश इससे बचा नहीं है। फिर भी मोदी सरकार के प्रयासों से भारत की स्थिति संभली हुई है। किंतु भारत का विपक्ष नकारात्मक राजनीति से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। निष्पक्षता के नाम पर नकारात्मक प्रचार करने वाले पत्रकार भी इसमें शामिल हैं। वह बता रहे है कि नौ वर्षों में महंगाई की दर सर्वाधिक है। किंतु उनके विश्लेषण में दुनिया की परिस्थिति शामिल नहीं है।

यूपीए सरकार तेल उत्पादक देशों व कम्पनियों का कई लाख करोड़ रुपये का कर्ज छोड़ गई थी। इसकी भरपाई भी वर्तमान सरकार को करनी पड़ रही है। इन दस वर्षों में अनेक संवेदनशील समस्याओं का समाधान हुआ। यह

सभी नरेंद्र मोदी सरकार के कारण ही संभव हुआ। यदि कोई अन्य सरकार होती तो इन मसलों पर चर्चा तक मुनासिब ना होती।

कांग्रेस के अनेक दिग्गज नेता श्रीरामजन्मभूमि की सुनवाई को टालने के लिए जमीन आसमान एक कर रहे थे। श्रीरामजन्मभूमि का विवाद पांच शताब्दी पुराना था। नरेंद्र मोदी सरकार ने कोर्ट में शीघ्र निर्णय का मार्ग प्रशस्त किया। इससे सदियों से लंबित समस्या का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ।

तीन तलाक पर प्रतिबंध भी नरेंद्र मोदी सरकार के कारण संभव हुआ। अनेक मुस्लिम देश इस पर रोक लगा चुके हैं। लेकिन भारत में रोक की बात को ही साम्प्रदायिक करार दिया जाता था। मोदी सरकार ने इसकी कोई चिंता नहीं की और कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने का काम किया।अनुच्छेद-370 और 35ए का विरोध करना भी साम्प्रदायिकता माना जाता था। सेक्युलर दिखने के लिए इन अलगाववादी प्रावधानों का समर्थन जरूरी था। इसके हटने पर गम्भीर परिणाम की चेतावनी तक दी गई। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने इसको हटा कर ही दम लिया। देश में आजादी के सात दशक बाद एक विधान एक निशान लागू हुआ।

इसी प्रकार पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगानिस्तान के उत्पीड़ित हिन्दू, बौद्ध, सिख, पारसी को न्याय मिला। नागरिकता संशोधन कानून लागू हुआ। इसका जिस प्रकार विरोध किया गया उससे जाहिर हुआ कि मोदी सरकार ना होती तो इन पीड़ितों की सुनने वाला कोई नहीं था। आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी गई। इसलिए देश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी ने अपनी दूरदर्शी नीतियों, समर्पण और टीम इंडिया की भावना के साथ देश के लोकतंत्र को एक नई दिशा दी है।

सरकार का प्रत्येक निर्णय लोक कल्याण व राष्ट्रीय हित के अनुरूप है। प्रधानमंत्री मोदी ने दशकों से लंबित फैसलों को लागू किया। कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। मगर भारत की अर्थव्यवस्था अब भी विकास की राह पर है। बीस लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के सहारे भारत की विकास यात्रा को नई गति मिली है तथा देश आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ा है।आजादी के बाद सात दशकों में देश के केवल साढ़े तीन करोड़ ग्रामीण घरों में ही पानी के कनेक्शन थे।सालों में भारत ने डिजिटल लेनदेन में दुनिया को नई दिशा दिखाने का काम किया है। रिकॉर्ड सैटेलाइट प्रक्षेपित किये जा रहे हैं। रिकॉर्ड सड़कें बनाई जा हैं। दशकों से लंबित अनेक योजनाएं पूरी की गई हैं। अनेक पुराने विवाद भी पूरी शांति और सौहार्द से सुलझाए गए हैं। पूर्वोत्तर से लेकर कश्मीर तक शांति और विकास का एक नया भरोसा जगा है। लेकिन नरेंद्र मोदी के शासन में साढ़े चार करोड़ घरों को साफ पानी कनेक्शन दिए गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान लागू की गई। इसके दायरे में पचास करोड़ लोग हैं।सालों में भारत ने डिजिटल लेनदेन में दुनिया को नई दिशा दिखाने का काम किया है। रिकॉर्ड सैटेलाइट प्रक्षेपित किये जा रहे हैं। रिकॉर्ड सड़कें बनाई जा हैं। दशकों से लंबित अनेक योजनाएं पूरी की गई हैं। अनेक पुराने विवाद भी

पूरी शांति और सौहार्द से सुलझाए गए हैं। पूर्वोत्तर से लेकर कश्मीर तक शांति और विकास का एक नया भरोसा जगा है। कोरोना काल में अस्सी करोड़ लोगों को निशुल्क राशन की व्यवस्था की गई। यह आज भी जारी है. जन औषधि दवा केन्द्र की संख्या अस्सी से बढ़कर पांच हजार हो गई। करीब सवा सौ नये मेडिकल कालेज खुले हैं। यूपीए के दस वर्ष में भारतीय रेल ने मात्र चार सौ तेरह रेल रोड ब्रिज और अंडर ब्रिज का निर्माण किया। मोदी सरकार ने इससे तीन गुना अधिक निर्माण किया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के पन्द्रह करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। यह दुनिया की सबसे सस्ती योजना है।

बिजली उत्पादन में चालीस प्रतिशत वृद्धि हुई। सोलर ऊर्जा में आठ गुना वृद्धि हुई। फसल बीमा योजना का लाभ पहले पचास प्रतिशत नुकसान पर मिलता था। अब किसान को तैतीस प्रतिशत पर भी मिल जाता है। सरकार ने यूरिया को नीम कोटेड किया जिससे इसकी कालाबाजारी खत्म हुई। देश मे अब यूरिया की कोई कमी नहीं होती।

पिछली सरकारों के समय बावन सेटेलाईट लॉन्च किये गए थे। मोदी सरकार अब तक देशी-विदेशी करीब तीन सौ सेटेलाईट लॉन्च कर चुकी है। यूपीए के समय ग्रामीण सड़क से जुड़ी बस्तियां पचपन प्रतिशत थीं। अब करीब पंचानबे प्रतिशत हैं।

नरेंद्र मोदी सरकार ने चालीस करोड़ लोगों के जनधन खाते खुलवाए। पहले ये लोग बैंकिंग सेवा से वंचित थे। आयुष्मान, उज्ज्वला और निर्धन आवास योजनाएं संचालित की गई। देश खुले में शौच से मुक्त हो गया।राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए कहा था कि सरकारी योजनाओं के एक रुपये में से केवल पन्द्रह पैसा ही गरीबों तक पहुंचता है। लेकिन वे बस कहकर ही रह गए, समाधान की दिशा में कुछ नहीं किया। समाधान नरेंद्र मोदी ने किया है। आज सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे लोगों के खातों में पहुंच रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां बेमिसाल है. विकास को नया आयाम मिला है. इसमें रेलवे भी शामिल है. रेलवे का विश्व स्तरीय विकास हो रहा है. यूपी के पहले विश्व स्तरीय गोमती नगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया. लखनऊ के सांसद और रक्षामंत्री स्टेशन परिसर में आयोजित समारोह में उपस्थित रहे. करीब 385 करोड़ रुपए की लागत से इसको तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने गोमतीनगर हाल्ट को स्टेशन बनाने की योजना की नींव रखी थी। 2018 में राजनाथ सिंह जी के प्रयासों से यह प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ था. पहले यहां मात्र तीन प्लेटफॉर्म थे. अब छह प्लेटफॉर्म निर्मित हो गए हैं. पहले यहां मात्र एक हाल्ट था।

स्टेशन का निर्माण दस एकड़ क्षेत्रफल में किया गया है। स्टेशन की उत्तर दिशा की टर्मिनल बिल्डिंग भूतल के साथ दो तल की और दक्षिण टर्मिनल की बिल्डिंग भूतल के साथ एक तल की है। एयर कानकोर्स बनाया गया है।

वेटिंग रूम, कैफेटेरिया, लाउंज की सुविधा भी होगी। नए टर्मिनल पर चौदह लिफ्ट और तेरह एक्सेलेटर है. सोलर एनर्जी से यह स्टेशन रोशन होगा. चार लाख वर्गफिट क्षेत्रफल में दो कामर्शियल ब्लाक भी विकसित

किए हैं।

हर ब्लॉक में डबल बेसमेंट के साथ भूतल और चार मंजिला निर्माण किया गया है। करीब उन्तीस हजार वर्गमीटर की डबल बेसमेंट की पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पांच सौ पैंतालीस रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और पंद्रह सौ रोड ओवर ब्रिज रोड अंडर ब्रिज की आधारशिला रखी। रेलवे से जुड़ी दो हजार से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभी तो इस सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत जून से होने वाली है। लेकिन अभी से भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के काम में तेजी दिखाई देने लगी है. दशकों तक रेलवे को हमारे यहां की स्वार्थ भरी राजनीति का शिकार होना पड़ा लेकिन अब भारतीय रेलवे देशवासियों की यात्रा में आसानी कर रही है. जिस रेलवे के हमेशा घाटे में रहने का रोना रोया जाता था, आज वह रेलवे परिवर्तन के सबसे बड़े दौर से गुजर रही है. आज करीब पैंतालीस हजार करोड़ की रेलवे परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है.

आने वाले 5 वर्षों में हजारों स्टेशनों के आधुनिक होने पर भारतीय रेल की क्षमता बढ़ेगी और निवेश की एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी। अब भारत अभूतपूर्व स्तर पर अभूतपूर्व गति से काम कर रहा है। छोटी-छोटी आकांक्षाओं से अलग होकर आज का भारत बड़े सपने देखने और उन सपनों को जल्द से जल्द साकार करने की ओर बढ़ चुका है। बजटीय आवंटन अधिक होने पर भी लीकेज से विकास बाधित होता है। यूपीए के मुकाबले नई रेलवे लाइनें बिछाने की गति दोगुनी हो गई है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के न्यू इंडिया विजन में विकास और लोक कल्याण का समावेश है। भारत को विकसित बनाने का संकल्प है। संकल्प को सिद्ध करने की इच्छाशक्ति है। उनकी नौ वर्ष की यह यात्रा यही प्रमाणित करती है। दूसरी तरफ विपक्ष के गठबंधन ने शब्दों के जुगाड़ से अपने लिए इंडिया नाम गढ़ लिया है। लेकिन उनकी कल्पना के इस इंडिया में विकास की कोई बात नहीं होती। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित बनने की दिशा में अग्रसर है। इसकी कार्ययोजना पर कार्य प्रगति पर है। इस नये भारत का रेलवे भी नया है, क्योंकि रेलवे में विकास की दृष्टि से भी दस साल बेमिसाल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी कि भारत विकसित होने के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा है। इसमें रेलवे का विकास का शामिल है। गति वर्ष

भारतीय रेलवे के इतिहास में नया अध्याय जुड़ा था. अमृत भारत रेलवे स्टेशन अभियान के अंतर्गत तेरह स्टेशन विकसित करने की योजना शुरू की गई.

प्रधानमंत्री मोदी ने इस परियोजना पहले चरण का गति वर्ष शुभारंभ किया था। पहले चरण मे पांच सौ आठ अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ। इन अमृत भारत स्टेशन के नवनिर्माण पर करीब पच्चीस हजार करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित थी. यह नया भारत है। सभी अमृत स्टेशन ग्रीन बिल्डिंग्स के मानकों को

पूरा करेंगे। अगले करीब छह वर्षों में भारत की रेलवे नेट जीरो एमिशन पर चलेगी। इसके साथ विपक्ष का इंडिया विकास को मुद्दा क्यों नहीं बनाना चाहता, यह भी स्पष्ट हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने दस वर्षों के दौरान रेलवे से सम्बन्धित कार्यों का उल्लेख किया। इतने मात्र से यूपीए सरकार बहुत पीछे छूट गई। नौ वर्षों के दौरान रेलवे में रिकॉर्ड धनराशि का निवेश किया गया। चालू वर्ष के लिए रेलवे को ढाई लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट दिया गया है। ये बजट दस वर्ष पहले की तुलना में पांच गुना ज्यादा है। रेलवे का समग्र विकास किया जा रहा है। लोकोमोटिव्स उत्पादन में भी दस वर्ष के दौरान नौ गुना की वृद्धि हुई है। आज देश में पहले की अपेक्षा तेरह गुना ज्यादा कोच बन रहे हैं। दस वर्ष में सोलर पैनल से बिजली बनाने वाले रेलवे स्टेशनों की संख्या भी बारह सौ से ज्यादा हो गई है। सभी स्टेशन ग्रीन एनर्जी बनाएंगे। ट्रेनों के करीब सत्तर हजार कोच में एलईडी लाइट्स लगाई जा चुकी हैं। ट्रेनों में बायो टॉइलेट की संख्या नौ वर्ष पहले के मुकाबले अब अट्ठाइस गुना ज्यादा हो गई है। सबसे विकास में पिछली सरकारों की विफलता का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि पूर्ववर्तियों के भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण के चलते विकास और लोक कल्याण के कार्य उपेक्षित हुए। ऐसी सरकारें दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकतीं। आज यही लोग नये भारत की विकास यात्रा में बाधा पैदा कर रहे हैं। विपक्ष का एक धड़ा आज भी पुराने ढर्रे पर चल रहा है। देश ने आज की और भविष्य की जरूरतों की चिंता करते हुए संसद की आधुनिक इमारत बनवाई। इस धड़े ने इसका भी विरोध किया। कर्तव्यपथ का विकास किया तो उसका भी विरोध किया गया। इन लोगों ने सत्तर साल तक वीर शहीदों के लिए वार मेमोरियल तक नहीं बनाया। हमने नेशनल वार मेमोरियल बनवाया, आलोचना करते वक्त इनको शर्म तक नहीं आई। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आज दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। हर हिन्दुस्तानी को गर्व होता है। कुछ राजनीतिक दल चुनाव के समय तो सरदार साहब को याद कर लेते हैं। लेकिन, आज तक इनका एक भी बड़ा नेता इस भव्य प्रतिमा के दर्शन करने नहीं गया। यह सच है कि साउथ अफ्रीका, यूक्रेन,पोलैंड, यूके और स्वीडन जैसे देशों में जितना रेल नेटवर्क है, उससे ज्यादा रेल ट्रैक हमारे देश में इन नौ वर्षों में बिछाया गया है। साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रिया जैसे देशों का जितना रेल नेटवर्क है, उससे ज्यादा ट्रैक भारत ने अकेले पिछले एक साल में बनाया है। भारत में आधुनिक ट्रेनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। प्लेटफॉर्मों पर बैठने के लिए बेहतर सीटें लग रही हैं। अच्छे वेटिंग रूम बनाए जा रहे हैं। हजारों रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा है। सरकार ने स्टेशनों को शहर और राज्यों की पहचान से जोड़ने के लिए वन स्टेशन,वन प्रॉडक्ट योजना भी शुरू की है। इससे पूरे इलाके के लोगों, कामगारों और कारीगरों को लाभ होगा। जिले की ब्रांडिंग भी अमृत रेलवे स्टेशन विरासत के प्रति गर्व की अनुभूति कराने वाले होंगे। इन स्टेशनों में देश की संस्कृति और स्थानीय विरासत की झलक दिखेगी। देश के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों और तीर्थ स्थानों को जोड़ने के लिए इन दिनों देश में भारत गौरव यात्रा ट्रेन और भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन भी चल रही है। रेलवे का कायाकल्प हो रहा है।

(विश्व प्रमोद डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन में रिसर्च एसोसिएट हैं।)

बीजेपी और कांग्रेस में किसने लोकतंत्र को सबसे ज्यादा रौंदा? 55 बनाम 10 साल के इतिहास से समझें

- देवेन्द्र कश्यप

कांग्रेस के रष्ट्रीय अध्यक्ष और विपक्ष के कई नेता बार-बार यह कह रहे कि भाजपा 2024 में सत्ता में आ गई तो देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अपने 55 साल के शासन में कांग्रेस ने 132 बार राष्ट्रपति शासन लगाया, राज्य सरकारें गिराईं, सीएम फ्रिक्वेंटली बदले, और नहीं तो इमर्जेंसी थोपी। फिर भी लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ तो भाजपा से इतना भय क्यों दिखा रही?

केंद्र की सत्ता में लगातार दूसरी बार काबिज भारतीय जनता पार्टी को 2024 में उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस बेचैन है। इसके लिए आधी-अधूरी कोशिशें भी उसकी ओर से हो रही है। दो बार कांग्रेस के पीएम फेस के रूप में आजमाए जा चुके राहुल गांधी कभी भारत जोड़ो तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के नाम पर साल भर से रुक-रुक कर देश भर में घूम रहे हैं। कांग्रेस ने विपक्षी दलों को एकजुट भी किया। पर इस एकजुटता का हासिल यह है कि यूपी में समाजवादी पार्टी द्वारा कुल 80 में 17 सीटें देने पर ही कांग्रेस को संतुष्ट होना पड़ा। ममता बनर्जी ने बंगाल की 42 में दो सीटें ही अभी तक देने की बात कही है। अब लालू यादव और अखिलेश यादव से कांग्रेस को आस है कि वे ममता से बात कर उसकी सीटों में थोड़ी और बढ़ोतरी करा देंगे। महाराष्ट्र में बात बन नहीं पा रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग-अलग ताल ठोकेंगी। दिल्ली में भी कांग्रेस को अदब से सात में तीन सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। बिहार में 40 सीटें हैं, जिनमें सात से 10 सीटें और झारखंड में 14 में सात से नौ सीटें कांग्रेस को मिलने वाली हैं।

कांग्रेस का राज 55 साल रहा

देश आजाद होने के बाद से लेकर 2014 तक कांग्रेस केंद्र की सत्ता में काबिज रही। इस दौरान हुए 16 आम चुनावों में कांग्रेस को छह में पूर्ण बहुमत हासिल किया। चार बार उसे गठबंधन सरकार का नेतृत्व का करने का अवसर मिला। आजाद भारत के पहले आम तुनाव में कांग्रेस को 364 सीटें मिली थीं। 16वीं लोकसभा में

कांग्रेस 44 सीटों पर आ गई। 17वीं लोकसभा में उसकी स्थिति थोड़ी सुधरी, पर गाड़ी 51 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई। कांग्रेस ने गांधी परिवार का वर्चस्व बनाए रखने के लिए सोनिया के बाद राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया, लेकिन वे भी कारगर साबित नहीं हुए। राहुल और सोनिया गांधी से पहले जवाहर नेहरू, कामराज, नीलम संजीव रेड्डी, इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी, राजीव गांधी जैसे दिग्गज कांग्रेस के अध्यक्ष रहे।

कांग्रेस को लोकतंत्र की चिंता

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को चिंता है कि कि 2024 में अगर भाजपा तीसरी बार सत्ता में आ गई तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। वे लोकतंत्र बचाने का 2024 के चुनाव को आखिरी मौका मानते हैं। वे कहते हैं कि लोकतंत्र को बचाने का यह आखिरी मौका है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो आने वाली पीढ़ियां पछताएंगी। ऐसा कहते समय वे भूल जाते हैं कि 55 साल तक बहुमत की सरकार चलाने और बाद के वर्षों में गठबंधन सरकार चलाने के बाद वे लोकतंत्र खत्म नहीं कर पाए तो महज 10 साल सत्ता में रहने वाली भाजपा कांग्रेस ने कैसे लोकतंत्र के लिए उन्हें किसी को यह भय नहीं खतरा नजर आने को खत्म कर देगी। हालांकि लगी है। आजाद लेकिन उसे इसकी भारी कीमत भारत में आरंभ से गांधी ने अपनी सत्ता बचाए रखने के लगातार पांच बार को उनका यह आचरण पसंद नहीं आया तो लोकसभा का चुनाव जीता। तब दिया। हुआ कि कांग्रेस देश से लोकतंत्र कांग्रेस ने ऐसी कोशिशें की भी, चुकानी पड़ी। साल 1975 में इंदिरा लिए देश में इमरजेंसी लगाई। जनता 1977 में कांग्रेस का सफाया ही कर

कांग्रेस ने इसकी कोशिश जरूर की

सच कहें तो कांग्रेस ने अपने शासन काल में इसकी कोशिश जरूर की। देश को बेवजह इमर्जेंसी का दंश झेलना पड़ा। कपड़ों की तरह मुख्यमंत्री बदले। विपक्ष शासित की कई राज्य सरकारें गिराईं। राष्ट्रपति शासन

तो कांग्रेस के लिए साधारण बात थी। कांग्रेस बता सकती है कि पिछले 10 साल के भाजपा के शासन में कितनी बार और कहां-कहां राष्ट्रपति शासन लगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे ठीक से समझाते हैं। राज्यसभा में उन्होंने हाल ही में कहा कि 'वो कौन लोग हैं, जिन्होंने आर्टिकल 356 का दुरुपयोग किया? एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार दुरुपयोग किया और वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। विपक्षी और क्षेत्रीय दलों की सरकारों को गिरा दिया गया। केरल में वामपंथी सरकार चुनी गई, जिसे नेहरू पसंद नहीं करते थे, तो उसे गिरा दिया गया। करुणानिधि जैसे दिग्गजों की सरकारें गिरा दी गईं। एनटीआर के साथ कांग्रेस ने ऐसा ही सलूक किया।'

90 बार चुनी सरकारें गिराईं

पीएम मोदी यह भी बताते हैं कि कांग्रेस ने क्षेत्रीय नेताओं को परेशान करने में कोताही नहीं की। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिराया गया। कांग्रेस ने डीएमके और वामपंथी सरकारों को खत्म किया। सच तो यह है कि देश में अब तक 132 बार अलग-अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। इनमें 90 बार राष्ट्रपति शासन तब लगा, जब केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी। पहली बार रष्ट्रपति शासन के लिए आर्टिकल 356 का प्रयोग पंजाब में 20 जून 1951 को हुआ था। पंजाब में 302 दिनों तक राष्ट्रपति शासन रहा। साल 1959 में केरल की चुनी हुई सरकार को भी आर्टिकल 356 का इस्तेमाल कर बर्खास्त कर दिया गया। 70 और 80 के दशक में विपक्ष की सरकारों को गिराने के लिए केंद्र सरकार ने संविधान के आर्टिकल 356 का दुरुपयोग खूब किया। इसके लिए सबसे ज्यादा आरोप पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर लगे।

(देवेंद्र नवभारत टाइम्स डिजिटल से जुड़े हैं। प्रस्तुत विचार लेखक के निजी हैं।)

Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

Dr. Syama Prasad Mookerjee

Research Foundation

9, Ashoka Road, New Delhi- 110001

Web :- www.spmrf.org, E-Mail: office@spmrf.org,

Phone: 011-69047014

@spmrfoundation